



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502

16 सितंबर 2021

आरबीआई बुलेटिन – सितंबर 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपने मासिक बुलेटिन का सितंबर 2021 का अंक जारी कर दिया। बुलेटिन में दो भाषण, पांच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

पांच आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. क्षेत्रवार बैंक ऋण आवंटन में परिवर्तन: वर्ष 2007-08 से हुई प्रगति; III. निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2020-21 में वृद्धि और 2021-22 के लिए दृष्टिकोण; IV. वित्तीय समावेशन योजना - वृद्धि पथ को प्रतिबिंबित करना; और V. भारत के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक।

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति

महामारी से पलायन वेग प्राप्त करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाएं उज्वल हो रही हैं क्योंकि दूसरी लहर खत्म हो गई है और भविष्य के लिए तैयारी युद्ध-अलर्ट स्थिति जैसी बनी हुई है। कुल मांग मजबूत हो रही है, जबकि आपूर्ति पक्ष पर आईआईपी और मुख्य उद्योग औद्योगिक गतिविधि में सुधार को दर्शा रहे हैं और सेवा क्षेत्र के संकेतक निरंतर सुधार की ओर इशारा कर रहे हैं। मुद्रास्फीति का प्रक्षेपवक्र अपेक्षा से अधिक अनुकूल रूप से नीचे जा रहा है। जैसा-जैसे महामारी के निशान मिट रहे हैं और उत्पादकता लाभ के साथ आपूर्ति की स्थिति बहाल हो रही है, वैसे-वैसे मुख्य मुद्रास्फीति की निरंतर सहजता की उम्मीद की जा सकती है, जो मौद्रिक नीति के वृद्धि-समर्थक रख को सुदृढ़ करेगी।

अर्थव्यवस्था की स्थिति के इस अंक का एक आकर्षण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और अंतर्निहित व्यापक आर्थिक प्रदर्शन के साथ उनके समंजस्य के बीच मौद्रिक नीति कार्रवाइयों में भिन्नता का विश्लेषण है। व्यापक निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- जिन देशों ने मौद्रिक नीति को कड़ा किया है, वे भी तेजी से बढ़ने/बढ़ने का अनुमान लगा रहे हैं, जिनमें से कई कमोडिटी और सेवा निर्यातक हैं, जो कमोडिटी की कीमतों में उछाल और रिवेंज टूरिज्म से लाभान्वित हो रहे हैं। कुछ ईएमई स्पिलओवर और यूएस में बेहतर वृद्धि संभावनाओं से हुए व्यापार लाभ के भी लाभार्थी हैं।
- उनमें से कुछ 2021 के सबसे आक्रामक दर वृद्धिकर्ता हैं और पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में शुद्ध निर्यात के लगभग दोगुना दर्ज किया है; इनमें से कुछ ईएमई महामारी के पूर्व के अपने उत्पादन स्तर पर दूसरी तिमाही तक ही ठीक हो गए थे।
- मध्यम से उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद जो देश ठहर से गए हैं, वे वो हैं जहां आर्थिक पुनर्बहाली पिछले साल की गिरावट के रूप में तेज नहीं है और/या पूरी तरह से टीकाकरण की गई आबादी के अनुपात के मामले में प्रतिकूल रूप से तुलना करते हैं।

- कुछ ईएमई ऐसे हैं, जिन्होंने और अधिक मौद्रिक प्रोत्साहन दिया है या सिद्धांत का पालन करने की प्रत्याशा में वे देश शामिल हैं जहां मुद्रास्फीति कम है, तथापि, यह बढ़ रही है; हाल के उच्च आवृत्ति संकेतकों के अनुसार, वे भी जो महामारी से तेजी से उबर तो गए थे, लेकिन वृद्धि ठप होती दिख रही है।

II. क्षेत्रवार बैंक ऋण आबंटन में परिवर्तन: वर्ष 2007-08 से हुई प्रगति

सभी क्षेत्रों में ऋण आबंटन में विकसित पैटर्न महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसका आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन पर प्रभाव पड़ सकता है। यह आलेख वर्ष 2007-08 के बाद से बैंकों के उधार व्यवहार के साथ-साथ औद्योगिक और गैर-औद्योगिक क्षेत्रों (कृषि और संबद्ध गतिविधियां, सेवाएं और व्यक्तिगत ऋण खंड) के बीच ऋण आबंटन में परिवर्तन की जांच करता है। यह ऋण सुपुर्दगी और क्षेत्रवार ऋण उठाव पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का अनुभवजन्य रूप से आकलन करता है।

मुख्य बातें:

- भारतीय अर्थव्यवस्था में 2007-08 से 2013-14 की अवधि के दौरान बैंक ऋण में वृद्धि हुई, क्योंकि खाद्येत्तर ऋण ने दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत ऋण वृद्धि से प्रेरित थी। तैंतीस चुनिंदा बैंकों के आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि दोनों प्रमुख-समूहों, जिसमें खाद्येत्तर ऋण में अपने हिस्से के आधार पर छह प्रमुख बैंक शामिल हैं, और अन्य-समूह जिसमें शेष बैंक शामिल हैं, ने आक्रामक रूप से औद्योगिक के साथ-साथ साथ ही अन्य क्षेत्रों को उधार दिया।
- हालांकि, बाद के वर्षों में, औद्योगिक क्षेत्र में निराशाजनक ऋण उठाव के कारण बैंक ऋण के क्षेत्रवार विनियोजन में एक उल्लेखनीय गुणात्मक बदलाव के साथ-साथ, ऋण वृद्धि लगभग पूरी तरह से गैर-औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से वैयक्तिक ऋणों द्वारा संचालित हो रही थी। बैंकों के प्रमुख समूह और दूसरे समूह, दोनों की सक्रिय भागीदारी गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण वृद्धि को बढ़ावा दे रही है।
- फिक्स्ड इफेक्ट पैनेल रिग्रेशन का उपयोग करते हुए एक प्रायोगिक अभ्यास से पता चला कि महामारी की अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। अन्य समूह द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से बड़े उद्योगों को दिया गया ऋण, कोविड-19 महामारी के कारण प्रमुख रूप से प्रभावित हुआ।

III. निजी कॉर्पोरेट निवेश: वर्ष 2020-21 में वृद्धि और वर्ष 2021-22 के लिए दृष्टिकोण

इस आलेख में, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा इंगित पूंजीगत व्यय (कैपेक्स चरणबद्ध योजनाओं पर परियोजना प्रस्तावों के आंकड़ों के आधार पर सन्निकट अवधि के निजी निवेश दृष्टिकोण का आकलन किया गया है। नई घोषणाओं की कम संख्या और कम परियोजनाओं के पूरा होने से यह परिलक्षित हुआ कि मुख्य भारतीय निजी कंपनियों के निवेश के इरादे सुस्त बने रहे। आलेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि महामारी की अनिश्चितताओं ने 2020-21 के दौरान नई परियोजनाओं के लिए वहन-क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और प्रक्रियाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में बाधा उत्पन्न की। 2021-22 में, नई परियोजनाओं की मांग पहले से ही प्रक्रियाधीन परियोजनाओं की प्रगति के साथ-साथ निजी निवेश दृष्टिकोण को आकार देगी।

IV. विकास पथ को दर्शाती - वित्तीय समावेशन योजना

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) बैंकों को देश भर में, विशेष रूप से अछूते/ अल्प-पहुँच वाले क्षेत्रों में, वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए एक योजनाबद्ध और सुनियोजित दृष्टिकोण रखने के लिए अधिकृत करती है। यह आलेख वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2020 के दौरान विभिन्न बैंक समूह(हों) और भौगोलिक क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के चुनिंदा पहुंच और उपयोग संकेतकों में देखी गई प्रगति और रुझानों पर प्रकाश डालता है।

मुख्य बातें

- हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए एक्सेस संकेतकों में वृद्धि धीमी रही है, लेकिन ग्रामीण शाखाओं में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के साथ वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उनका दबदबा बना हुआ है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान पीएसबी और आरआरबी की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) ने (ग्रामीण शाखाओं और बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट (बीसी) आउटलेट दोनों में) उच्च वृद्धि दर्ज की है।
- पूर्वी और मध्य क्षेत्र, जो ऐतिहासिक रूप से पहुंच संकेतकों में खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, इन क्षेत्रों में बीसी मॉडल के उल्लेखनीय विस्तार से लाभान्वित हुए हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, मूल बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) में सबसे अधिक वृद्धि पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में दर्ज की गई है।
- इस अवधि के दौरान देश के ग्रामीण और शहरी दोनों हिस्सों में बीसी आउटलेट की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण पीवीबी द्वारा बीसी मॉडल को अपनाना है।
- बीसी मॉडल की पहुंच के विस्तार के साथ, इसकी उपयोगिता भी बढ़ी है, जो बीसी के माध्यम से खोले जा रहे 56 प्रतिशत से अधिक बीएसबीडीए में परिलक्षित होता है। इसके अलावा, बीसी आउटलेट के माध्यम से किए जा रहे लेनदेन के मूल्य और मात्रा दोनों में कई गुना वृद्धि हुई है, जिससे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में बीसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का संकेत मिलता है।

V. भारत के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक

व्यापक, समावेशी और सतत विकास के लिए अधिक वित्तीय समावेशन (एफआई) महत्वपूर्ण है। इसलिए, एफआई को बढ़ावा देने के लिए की गई नीतिगत पहलों की प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए एफआई का एक उपाय आवश्यक है। 97 संकेतकों के आधार पर एक बहुआयामी समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स) का निर्माण किया गया है, जो वित्तीय समावेशन की मात्रा को मापता है और उपलब्धता, पहुंच में आसानी, उपयोग, असमानता और सेवाओं में कमी, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उत्तरदायी है।

यह आलेख 'पहुंच', 'उपयोग' और 'गुणवत्ता' आयामों, भार वितरण, चयनित संकेतकों के लिए वांछित लक्ष्य, और इन संकेतकों को एक समग्र सूचकांक में संयोजित करने की पद्धति के लिए संकेतकों के संदर्भ में FI-सूचकांक के निर्माण पर आधारित है। इस प्रकार निर्मित FI-सूचकांक 0 और 100 के बीच एक ही संख्या में वित्तीय समावेशन के विभिन्न आयामों पर जानकारी प्राप्त करता है - जहां 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्कार का प्रतिनिधित्व करता है और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। 0 से 100 के पैमाने में, 2021 के लिए तीन उप-सूचकांक जैसे 'एक्सेस', 'यूसेज' और 'क्वालिटी' के साथ वार्षिक एफआई-इंडेक्स 53.9 था, जो मुख्य रूप से एक्सेस सब-इंडेक्स द्वारा संचालित था, जो सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से देश में वित्तीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में अब तक की गई पर्याप्त प्रगति को दर्शाते हुए 73.3 पर रहा।

आलेख के खंड वित्तीय समावेशन पर कुछ मौजूदा अध्ययनों की समीक्षा करते हैं, एफआई-इंडेक्स के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली पर चर्चा करते हैं, परिणामों पर कब्जा करते हैं और आगे के रास्ते पर ध्यान देते हैं।

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/872

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक